Shrimati Renu Chakravartty: We do not want that.

Shri Kanungo: Obviously, the import duty is 100 to 150 per cent. more. So, we do not have those figures here.

Coir Research Institute

+

Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hasda:

Will the Minister of **Commerce and Industry** be pleased to state:

(a) whether the proposed Coir Research Institute with a model factory attached to it has since been started in West Bengal;

(b) whether training arrangements for the industry will also be arranged;

(c) when the proposed show-room and sales depot of Coir industry products will be opened in Calcutta; and

(d) the amount spent in the State of West Bengal by the Coir Board since its inception?

The Minister of Industry (Shri Manubhai Shah): (a) No, Sir. The scheme has been only just sanctioned.

(b) Yes, Sir; separately in the training-*cum*-production centres proposed to be started by the State Government.

(c) Towards the end of this year.

(d) The State Government are just starting to take interest in Coir development and are shortly drawing up plans for consideration of the Coir Board.

With your permission Sir, I may also add that provision for coir development in the Second Plan for West Bengal is Rs. 6 lakhs.

Shri S. C. Samanta: May I know when the decision to open a coir reseach institute in West Bengal was taken, and why so much delay has been caused?

Shri Manubhai Shah: This plan was drawn up at the beginning of the year, and the sanction was accorded only last month.

Shri S. C. Samanta: May I know whether there is any interim arrangement for the training of workers in Kerala or in Madras?

Shri Manubhai Shah: Yes, we are arranging in the production-*cum*-training centres in all the four States for the training of boys for this institute.

Shri R. Ramanathan Chettiar: In view of the coir industry being situated in the West Coast of India, what action do Government propose to take to set up another research institute in the West Coast?

Shri Manubhai Shah: After going into the experience of these two Institutes, the Coir Board will certainly look into the question of developing such Institutes elsewhere also if necessary.

Shri Narayanankutty Menon: Are Government aware that the retail selling prices of manufactured coir mattings in the show room maintained by the Coir Board in different places are 25 per cent. higher than the ordinary market rates?

Shri Manubhai Shah: That is not correct But the prices vary from quality to quality. Some of the high qualities which are very much in demand naturally have higher prices than inferior qualities

बर्मा में भारतीय

*२० श्री भक्त दर्शन : क्या प्रधान मंत्री १ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १८३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गत महायुद्ध में बर्मा में भारतीयों को जो हानि उठानी पडी थी उसकी क्षतिपूर्ति कराने की दिशा में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : इस मामले में तब से अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है ।

श्री भक्त दर्शन : सरकार की ओर से जो उत्तर दिया या है उसका क्या यह अर्थ है कि अब इस सम्बन्ध से कोई आशा न की जाए यानी बर्मा से जिन भारतीयो को आना पडा है उनको कोई भी मुआवजा नही मिलने वाला है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : बहुत ज्यादा आशा करना शायद कारामद न हो ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान मे यह बात आई है कि हजारो भारतीयो को लाखो और करोडो रुपये का नुकसान उठा कर भारत मे आना पडा और आज वे दरबदर घूम रहे है । क्या उनके पुनर्वास के बारे मे कोई कदम उठाये जा रहे है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : आपका जो सवाल था वह युद्ध के जमाने मे ताल्लुक रखता था और जो बाते हुई है वे तो हुई ही है ।

Shri R. Ramanathan Chettiar: What is the total amount of compensation that has been paid by the Government of Burma to Indian nationals owning land and who have been dispossessed of those lands by the Land Nationalisation Act?

Mr. Speaker: That is an absolutely different question This refers to compensation for losses during the war.

श्री भक्त दर्शन : डेढ वर्ष पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय संसदीय सचिव ने फरमाया था कि जापान ने बर्मा को युद्ध के जमाने में हुई क्षति के लिए २५० मिलियन डालर देने का वादा किया है । क्या उस क्षतिपूर्ति में से भारत के जिन लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है कुछ रुपया दिलाने की कोशिश की जा रही है ?

Shrimati Lakshmi Menon: Reparations paid by the Japanese Government are in the form of goods and services.

आणविक परीक्षण

+

*११ { श्री रूप नारायण :
श्री विभूति मिश्र :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र-संघ महासभा के वर्तमान सत्र मे आणविक परीक्षणो पर तत्काल रोक लगाने के बारे में कोई प्रस्ताव रखे है , और

(ख) यदि हा, तो वे प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) (क) जी, हा । इस प्रस्ताव की एक प्रति हम लोक सभा की मेज पर रख रहे हैं । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३]

(ख) भारतीय प्रस्ताव राजनीतिक समिति (पोलिटिकल कमेटी) मे गिर गए थे । जनरल असेम्बली के पूर्ण अधिवेशन के सामने यह विषय अभी आना है ।

श्री रूप नारायण : क्या भारत सरकार ने यह जानने की कभी कोशिश की है कि किस किस राष्ट्र ने हमारे प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू जी हा, यह बात तो छप जाती है और सब को मालूम है । यह चीज कभी छिपी नही रहती है ।

श्री रूप नारायण . क्या मैं जान सकता हू कि इस प्रस्ताव के विषय में, रूस, अमरीका और ब्रिटेन, इन तीनो देशो की क्या राय है और इन में से कौन सा राष्ट्र या कौन सा देश इस के पक्ष में है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस वक्त मेरे पास कोई फेहरिस्त नही है । मगर आप चाहें तो मैं आपको भिजवा दूगा या मेज पर रख